न्यायमूर्ति एम. जयापॉल के समक्ष,

जसबीर सिंह-अपीलकर्ता

बनाम

नीलम @निर्मला और अन्य--प्रतिवादी

FAONo. 2011 का 3173

3 जुलाई 2012

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 149(2)ए(आई) - वाहन के मालिक को चालक के साथ संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि चालक के पास फर्जी लाइसेंस था - मालिक द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होने का आरोप लगाते हुए पुरस्कार को चुनौती दी गई - आयोजित यदि मालिक ने खुद को संतुष्ट कर लिया है कि ड्राइवर सक्षम है और उसके पास लाइसेंस है, तो धारा 149(2)ए(आई) का कोई उल्लंघन नहीं है - ड्राइवर 20 साल से अधिक समय से मालिक है - केवल बीमा कंपनी ही इसकी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी है। ड्राइविंग लाइसेंस - बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि मालिक को पता था कि देनदारी से बचने के लिए ड्राइवर के पास फर्जी लाइसेंस है - अपील की अनुमति - बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

माना गया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में। लेहरू और अन्य, जेटी 2003 (2) एससी 595, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि यह मालिक नहीं है जिससे सहायता मांगने वाले ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की उम्मीद की जाती है। पूरे देश में सक्षम प्राधिकारी। 'बीमा कंपनी यह स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है कि दायित्व से बचने के लिए वाहन के मालिक को अपने ड्राइवर के पास मौजूद नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अच्छी तरह से पता था।

(पैरा 8)

आगे आयोजित किया गया। ट्रिब्यूनल का यह निर्णय कि अपीलकर्ता और उसका ड्राइवर दावेदारों को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे, को खारिज कर दिया गया है और प्रतिवादी नंबर 6- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी.एस. पुनिया।

हर्ष अग्रवाल, वकील, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए।

न्यायमूर्ति एम. जयापॉल,

(1) वाहन के मालिक जयबीर सिंह ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले से व्यथित होकर उसे दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी मानते हुए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

(2) ट्रिब्यूनल ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, मोटर वाहन विभाग, कटक द्वारा जारी किए गए Ex.R6 और R8 को सूचित करते हुए सूचित किया कि घनशाम के नाम पर जारी किया गया कथित ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, जिसे फास्टन करने के लिए चुना गया। वाहन के चालक और मालिक पर दायित्व।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता, जो वाहन का मालिक है, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि यह केवल बीमा कंपनी है जो ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी है और पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज करें। उनका आगे यह कहना है कि मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने दुर्घटना से पहले पिछले 20 वर्षों तक घनशाम को नियुक्त किया था। यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वह ड्राइवर के साथ मिला हुआ था और उसने जानबूझकर उस ड्राइवर को वाहन

चलाने की अनुमति दी थी जिसके पास फर्जी लाइसेंस था। इसलिए, उनका कहना है कि जिस बीमा कंपनी ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन नहीं किया है, वह दावे का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है।

(4) इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने यह सत्यापित करने के लिए कुछ जांच की थी कि घनशाम द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस असली था या नहीं। उन्होंने इस तथ्य के बारे में बात नहीं की थी कि ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने से पहले उन्होंने घनशाम की क्षमता का परीक्षण किया था। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे, उनका तर्क है।

(5) संपूर्ण अभिलेखों का गहन अध्ययन करने पर, यह पाया गया कि बीमा कंपनी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 6 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, मोटर वाहन विभाग, कटक से एक रिपोर्ट मिली है और इसे प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ट्रिब्यूनल के समक्ष R6. ट्रिब्यूनल ने उक्त प्राधिकारी से एक रिपोर्ट भी तलब की और उसे प्रदर्शनी आर8 के रूप में प्रदर्शित किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, मोटर वाहन विभाग, कटक (उड़ीसा) द्वारा जारी उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि घनशाम के नाम पर जारी किया गया मूल ड्राइविंग लाइसेंस नकली था। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियाँ यह स्थापित करेंगी कि अपराधी वाहन का चालक घनशाम, जिसके पास केवल एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस था, को यहाँ अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया था।

(6) अब निर्धारण के लिए मुद्दा यह उठता है कि क्या ऐसे तथ्यात्मक परिदृश्य में बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने इस आशय का साक्ष्य दिया है कि ड्राइवर घनशाम घटना से पहले 20 वर्षों तक कार्यरत था। उन्होंने घनशाम द्वारा उत्पादित लाइसेंस के बाद

के नवीनीकरणों का भी सत्यापन किया था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता द्वारा घनश्याम को 20 वर्षों तक नियोजित किया गया था, यह दर्शाता है कि घनशाम ने वाहन के मालिक, यानी अपीलकर्ता को आपत्तिजनक वाहन चलाने की अपनी क्षमता के संबंध में पूरी तरह से संतुष्ट किया था। जैसा कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने ठीक ही बताया है, बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दूर-दूर तक यह पता चले कि अपीलकर्ता को यह अच्छी तरह से पता था कि घनशाम के पास फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस है और उसने उसे वाहन चलाने के लिए नियुक्त किया था।

(7) इस संदर्भ में, अपीलकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिड में। लेहरू और अन्य के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"20. जब कोई मालिक किसी ड्राइवर को काम पर रखता है, तो उसे यह जांचना होगा कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। यदि ड्राइवर ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस पेश करता है, जो देखने में असली लगता है, तो मालिक से यह पता लगाने की उम्मीद नहीं की जाती है कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है या नहीं। इसके बाद मालिक ड्राइवर का परीक्षण करेगा। यदि उसे पता चलता है कि ड्राइवर वाहन चलाने में सक्षम है, तो वह ड्राइवर को काम पर रखेगा। हमें यह अजीब लगता है कि बीमा कंपनियां मालिकों से अपेक्षा करती हैं कि वे पूरे देश में फैले आरटीओ से पूछताछ करें कि उन्हें दिखाया गया ड्राइविंग लाइसेंस वैध है या नहीं। इस प्रकार जहां मालिक ने खुद को संतुष्ट कर लिया है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है और वह सक्षम रूप से गाड़ी चला रहा है। धारा 149(2)(ए)(आई) का कोई उल्लंघन नहीं। बीमा कंपनी तब दायित्व से मुक्त नहीं होगी। यदि अंततः यह पता चलता है कि लाइसेंस नकली था तो बीमा कंपनी तब तक उत्तरदायी बनी रहेगी जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि मालिक /बीमाधारक को पता था या उसने देखा था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामले में

भी बीमा कंपनी निर्दोष तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी रहेगी, लेकिन वह बीमाधारक से वसूली करने में सक्षम हो सकती है। यही वह कानून है जो स्कैंडिया के सोहन लाल पासी और कमला के मामले में बनाया गया है। हम उसमें व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हैं और अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता। "

(8) उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि पूरे देश में सक्षम प्राधिकारी की सहायता मांगने वाले ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की अपेक्षा मालिक से नहीं की जाती है। बीमा कंपनी यह स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है कि दायित्व से बचने के लिए वाहन के मालिक को अपने ड्राइवर के पास मौजूद नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अच्छी तरह से पता था।

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य के मामले में भी निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"108 (iii)। पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन, उदाहरण के लिए, धारा 149 की उपधारा (2) (ए) (आई) में निहित ड्राइवर के अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के कारण उसे अयोग्य घोषित करना, बीमाधारक द्वारा किया गया साबित होना चाहिए। बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए। प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता का मात्र अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर या प्रासंगिक समय पर ड्राइवर के लिए अयोग्य नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा। "

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में पूर्व निर्णय में निर्धारित अनुपात को दोहराया गया है।

(10) उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल ने वाहन के मालिक को दावेदारों को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी ठहराकर गलती की है। प्रतिवादी नंबर 6-बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

(11) इसलिए, ट्रिब्यूनल का यह निर्णय कि अपीलकर्ता और उसका ड्राइवर दावेदारों को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे, को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी नंबर 6- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

(12) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है.

(13) रुपये की राशि. अपील दायर करते समय अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई 25,000/- की राशि उसे वापस लौटाने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh